IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 22 | सांचौर, शुक्रवार, 15 नवंबर 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

कर्मचारी समृद्धि ऋण योजना लागू

बारां,। केंद्रीय सहकारी बैंक बारां के कार्यक्षेत्र अर्थात बारां जिले में निवास करने वाले सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं बैंक कर्मचारियों की भौतिक आवश्यकताओं, व्यवसाय वृद्धि, बच्चों की शिक्षा, शादी, सामाजिक उत्सव एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में सक्षमता बनाए रखने हेतु बैंक द्वारा कर्मचारी समृद्धि ऋण योजना लागू की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रबन्ध निदेशक सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य सरकार, भारत सरकार के गजेटेड अधिकारियों का अधिकतम राशि रुपये 10 लाख, नॉन गजेटेड एवं अन्य पात्रता धारकों को अधिकतम 5 लाख तक का ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

फर्म को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के दिए निर्देश

जालोर। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने जिला मुख्यालय पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक जालोर परिसर में वीरमदेव कान्हडदेव चौहान पैनोरमा के लिए आवंटित भूमि स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने वीरमदेव कान्हडदेव पैनोरमा के संबंध में एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने पर असंतोष जताते हुए संबंधित फर्म को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप सभापति अम्बालाल व्यास, जालोर तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित, विशेषाधिकारी कुलदीप देवल, एडवोकेट सुरेश सोलंकी, केशव व्यास, दिनेश महावर, नाथु सोलंकी आदि उपस्थित रहे।

पंचायतीराज मंत्रालय नई दिल्ली में करेगा वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों और कई मंत्रालयों के अफसर करेंगे मंथन

पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण को बनेगा फ्रेमवर्क

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को केंद्र सरकार शासन व्यवस्था में भी धरातल पर उतारना चाहती है। इसी सोच के अनुरूप पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय ने कमर कसी है। इस दिशा में पहल करते हुए मंत्रालय केंद्रीय वित्त आयोग के सहयोग से राज्य वित्त आयोगों, संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों को सहभागी बनाते हुए 14 नवंबर को नई दिल्ली में वित्त आयोग सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसमें विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा जो मंथन किया जाएगा, उसके आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। विकास के लिए हस्तांतरण थीम पर वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया और पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों, पंचायतीराज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों सहित संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। पंचायतीराज मंत्रालय के अनुसार, सरकार चाहती है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य वित्त आयोगों का ससमय गठन हो, पंचायतों या ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण हो और निकायों को स्वायत्त व आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास के प्रति उनके उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाएं। मगर, मंत्रालय का मानना है कि व्यवस्था तय होने के बावजूद वित्तीय अधिकारों व कार्यबल के हस्तांतरण और अनुदान के संबंध में कई राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके क्या कारण हैं और इन्हें दूर करते हुए कैसे राज्य वित्त आयोगों के समयबद्ध गठन, सिफारिशों को लागू करने और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया जा सकता है, इस पर संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों के विचार लिए जाएंगे। उसके आधार पर ही पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। केंद्र का मानना है कि केंद्र या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और विकसित भारत के संकल्प में ग्रामीण भारत को साथ जोड़ने में सशक्त पंचायतें ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

गुन्दाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गुन्दाऊ

किसानों से अपील
एकमुश्त समाधान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की अरणाय शाखा में सपर्क करें।

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्रीमति सीता कंवर
अध्यक्ष

श्री जगदीश सिंह चंपावत
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

श्री चेन्ननाथ
सहायक व्यवस्थापक

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर किए जाने का नियम

2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ऑडिट कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में संचालित 8207 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में से 6143 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षा का कार्य पूर्ण हुआ हैं जबकि 2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में ऑडिट कार्य शेष हैं, जिसको लेकर सहकारिता विभाग पंजीयक मंजू राजपाल ने गत दिनों समस्त क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी एवं विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां को पत्र लिखा हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54(3) के तहत प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर किए जाने का नियम निर्धारित हैं, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंकेक्षणों द्वारा समितियों की निर्धारित समयावधि में ऑडिट नहीं कर अधिनियम के प्रावधनों एवं विभागीय पैनल पंजीकरण की शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा हैं । ऐसी स्थिती में अंकेक्षकों, सीए/सीए फर्मस् को आंवटित समितियों की ऑडिट 30 नवंबर 2024 तक पूर्ण करने वही इस समयावधि में ऑडिट पूर्णनहीं करने वाले सीए/सीए फर्मस् के विरुद्ध विभागीय पैनल की शर्तो के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं ।

12909 समितियां ऑडिट से शेष

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अलावा अन्य 23327 सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से 10418 समितियों की ही विछीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट संपन्न हुई, वही 12909 समितियां ऑडिट से शेष हैं, इस स्थिती में भी सहकारिता विभाग पंजीयक ने 15 दिसबर तक ऑडिट पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस निर्धारित समयावधि में ऑडिट पूर्ण नहीं करने वाले सीए/सीए फर्मस् के विरूद्ध विभागीय पैनल की शर्ता के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए है।

विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका महत्तवपूर्ण

चूरू। जिले में 71वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। इस क्रम में, दी चूरू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में सहकारिता मंत्रालय की नवीन पहलों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही इस वर्ष के सहकार सप्ताह की थीम 'विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका' पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने पर विचार-विमर्श हुआ।

लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण, समृद्धि और भरपूर फसल उत्पादन की दिशा में पूरी गंभीरता से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों के विगत वर्षों के लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्षों से लंबित किसानों के बीमा क्लेमों को शीघ्र वितरित कराये जाने हेतु कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ0 किरोड़ी लाल द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा केपनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रूपये के बीमा क्लेम लंबित है। लंबित क्लेमों में बैंक खाता सेबन्धी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। लंबित बीमा क्लेम के निस्तारण हेतु कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा कैप लगाकर प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, नवीन बैंक खाते का विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे कर संबन्धित कमियों को दूर कर, लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी। गत वर्षो के लंबित बीमा क्लेम वितरित कराने के निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है जिनके भुगतान बैंक खाता व आधार सत्यापन के अभाव में विफल हो गये थे। इस हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संबन्धित बीमा केपनी के साथ बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत नवेबर 2024 तक लंबित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

नाममात्र सदस्यों को मिल पाया फसली ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

अब तक 681 सदस्यों को मिला ऋण

अपेक्स बैंक की ओर से संचालित सहकारी ऋण पोर्टल से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अब तक 681 किसानों को ही ऋण वितरित किया गया हैं, जबकि जिले में 1 लाख 32 हजार 241 से किसान सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं ।

जालोर । जालोर एवं सांचौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा सरकार की ब्याज मुक्त महत्वपूर्ण योजना में रबी सीजन में ऋण वितरण प्रक्रिया को त्वरित गति से संपन्न करवाकर अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीसीबी प्रबंध निदेशक जमीनी स्तर पर जुझ रहें हैं, कारण हैं कि प्रधान कार्यालय से लेकर सीसीबी की शाखाओं में स्टाफ की कमी के चलते जरुरतमंद को फसली ऋण मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस रबी सीजन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा ऋण वितरण कार्य के प्रति शिथिलता बरती जा रही हैं, वही सीसीबी की संचालित शाखाओं में पदस्थ शाखा प्रबंधक ब्याज मुक्त योजना में फसली ऋण वितरण कार्य के प्रति रुझान नहीं दिखा रहें है। हालांकि गत दिनों सीसीबी प्रबंधन की ओर से रबी सीजन में ऋण वितरण को लेकर आदेश जारी हुआ, दरअसल सीसीबी प्रबंधक ऋण अनुभाग ने समस्त शाखा प्रबंधकों को एक अतिआवश्यक आदेश जारी कर 2024-25 की बुवाई को मध्यनजर रखकर अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रारंभ कर उसकी सूचना प्रधान कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए थे ।

एनएफएसए से अपात्र उपभोक्ताओं की छंटनी के लिए चलेगा अभियान

छंटनी अभियान से पूर्व अपात्र उपभोक्ता स्वेच्छा से एनएफएसए का लाभ छोड़ने के लिए कर सकेंगे आवेदन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र उपभोक्ताओं की छंटनी के अभियान से पहले स्वेच्छा से एनएफएसए में राशन का गेहूं छोड़ने वालों से आवेदन मांगे गए हैं। संभवतः स्वेच्छा से आवेदन करने वाले अपात्र उपभोक्ता विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अपात्रों का छंटनी अभियान शुरू किया गया हैं। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने 29 अक्टूबर को पत्र जारी करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों में निष्कासन की श्रेणी में आने वालों को स्वेच्छा से नाम हटवाने का अवसर दिया है। कोई लाभार्थी निष्कासन की श्रेणी में आने के बाद भी एनएफएसए से जुड़ा हुआ पाये जाने पर रसद विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई के साथ वसूली के दायरे में आ जाएगा। वहीं स्वेच्छा से नाम कटवाने वालों को विभागीय कार्रवाई से मुक्त रखा जाने की उम्मीद है।

कर्मचारी से हो गई वसूली

राज्य में 5 वर्ष पहले एनएफएसए में एक रूपये किलो का गेहूं उठाने वाले लाखों राज्य कर्मचारी और फिर केन्द्र सरकार के कर्मचारी के जुड़े होना पाया गया था। रसद विभाग ने योजना का आधार से जुड़ते ही लाखों राज्य व केन्द्र कर्मचारी और उनके परिजन वसूली के दायरे में आ गए। विभाग ने वसूली की कार्यवाही करते हुए एक रूपये किलो में मिलने वाले राशन के गेहूं की 27 रूपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की गई थी।

वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वाली

किसानों से अपील
एकमुश्त समाधान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की धुबांड़िया शाखा में सपर्क करें।

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री हीराराम चौधरी
अध्यक्ष

श्री डायाराम देवासी
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

श्री मुकेश कुमार
सहायक व्यवस्थापक

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

सहकारिता विभाग ने विधायक के सवाल पर बताया कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का फसली ऋण देने के लक्ष्य

अगले पांच वर्षो में किसानों को मिलेगा शुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ रुपए का फसली ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

लक्ष्य में नहीं हुई बढ़ोतरी

प्रदेश में ब्याज मुक्त योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वितरित होने वाले फसली सहकारी ऋण को लेकर गत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में 23 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, वर्तमान सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की और सरकार ने बजट घोषणा में 23 हजार करोड़ का ही लक्ष्य निर्धारित किया हैं। इसके अलावा ब्याज मुक्त योजना से 5 लाख नए किसानों को जोड़ने की घोषणा हुई, जिससे प्रेरित होकर कई किसानों ने ऋण के लिए आवेदन किया, जब ऋण देने की बारी आई तो किसान सदस्यों को 1.50 लाख की साख सीमा स्वीकृत कर महज 15 हजार ऋण थमा दिया गया, उसमें से भी सहकार जीवन सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा भी अनिवार्य रुप से करवाना पड़ रहा हैं । जिससे लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी जमीन में फसल बुवाई के लिए मिलने वाली फसली ऋण राशि से पर्याप्त खाद-बीज भी बाजार भाव में नहीं मिल पा रहें है।

जयपुर । प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से सीजनली ब्याज मुक्त फसली ऋण मुहैया कराया जा रहा हैं, निर्धारित तिथि पर ऋण का चुकारा करने वाले किसानों को शुन्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिल रहा हैं, राज्य सरकार की इस योजना का क्रियावन्यन सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा हैं, जहां गांव स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को उनकी साख के अनुसार अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं, आने वाले पांच वर्षो में ब्याज मुक्त योजना के तहत सरकार एक लाख करोड़ का फसली ऋण देने पर विचार कर रही हैं, ऐसा सहकारिता विभाग ने विधानसभा में एक अतांराकित प्रश्न के प्रतिउत्तर में कहा हैं, दरअसल, विधायक मनीष यादव ने सोलहवी विधानसभा के दूसरे सत्र में 23 जून 2024 को किसानों को ऋण देने की कार्ययोजना से संबंधित प्रश्न अंकित कर सहकारिता विभाग से जवाब मांगा था, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन से लेकर 17 जून तक सीसीबी से संबंध सहकारी समितियों द्वारा 15 दिसबंर 2023 से 31 मार्च 2024 यानि रबी सीजन में 16 लाख 21 हजार 134 किसानों को 6744.95 करोड़ तथा 1 अप्रैल 2024 से 17 जून 2024 यानि खरीफ सीजन में 17 लाख 45 हजार 518 किसानों को 6871.16 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया हैं, इन किसानों को जिला स्तरीय तकनीकि समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कृषक की जोत, उसके द्वारा बोई जाने वाली फसलों एवं केंद्रीय सहकारी बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। वही, विधायक के मूल सवाल पर विभाग ने लिखित में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 23 हजार करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं ।

23 हजार करोड़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य निर्धारित

6744.95 करोड़ का ऋण 15 दिसबंर 2023 से 31 मार्च 2024 तक वितरित

6871.16 करोड़ का ऋण 1 अप्रैल 2024 से 17 जून 2024 तक वितरित

स्वीकृत साख सीमा के अनुरुप नहीं दिया जा रहा ऋण

प्रदेश की बाड़मेर एवं जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक पिछले छह वर्षो में करीब 4 लाख 41 हजार 691 किसानों में से एक भी किसानों को उसकी साख सीमा के अनुरुप 1.50 लाख का पूरा ऋण नहीं दे पाई हैं, जब भी इसकी चर्चा होती हैं, तो विभाग एवं सीसीबी द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है।

असहाय नगर निकाय

इस पर हैरानी नहीं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने यह पाया कि देश के अधिकांश नगर निकाय न तो अपने स्रोतों से धन जुटाने में समर्थ हैं और न ही आवंटन के जरिये मिले पैसे का पूरा उपयोग कर पाने में। स्पष्ट है कि ऐसे में शहरों की स्थिति सुधरने की जो आशा की जा रही है, वह पूरी होने वाली नहीं है। कैग की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों को वांछित अधिकार देने को तैयार नहीं। वे इस पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं कि नगर निकाय कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह विचित्र है कि जो राज्य सरकारें संघीय ढांचे का हवाला देकर केंद्र पर यह आरोप लगाती रहती हैं कि वह उन्हें पूरी स्वतंत्रता से काम नहीं करने देती, वे अपने नगर निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिलीं आवश्यक शक्तियां देने को तैयार नहीं। आखिर आवश्यक अधिकारों के अभाव में नगर निकाय अपना काम सही तरह से कैसे कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि शहरी निकाय एक तरह से शासन की तीसरी इकाई हैं और उनका समर्थ होना आवश्यक है। नि:संदेह उन्हें समर्थ बनाने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए। यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें इनमें से भी कोई काम नहीं कर रही हैं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के जरिये राज्यों के समक्ष ऐसा कोई उदाहरण पेश करे कि शहरी निकायों को किन अधिकारों से लैस होना चाहिए, उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए और खुद को आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बनाना चाहिए ? यह समझा जाना चाहिए कि शहरों की सूरत तब तक नहीं संवर सकती, जब तक नगर निकाय प्रशासनिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनने के साथ ही शहरों के विकास की ऐसी योजनाएं बनाने में समर्थ नहीं होते, जो दीर्घकालिक और भविष्य की जरूरतों को पूरी करने वाली हों। चूंकि आम तौर पर शहरी विकास की ज्यादातर योजनाएं समस्याओं का फौरी समाधान करती दिखती हैं, इसलिए तमाम विकास कार्यों के बाद भी शहरों में विभिन्न समस्याएं सदैव सिर उठाए हुए दिखती हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि किस तरह नए बने रास्ते, लाईओवर, बाईपास आदि किस तरह कुछ समय बाद अपर्याप्त सिद्ध होने लगते हैं? पता नहीं क्यों आज भी शहरी योजनाएं यह ध्यान में रखकर नहीं बनाई जातीं कि आज से 50-60 साल बाद आबादी क्या होगी और उसके लिए कैसा आधारभूत ढांचा चाहिए होगा ? कभी-कभी तो यह लगता है कि इस पर कोई विचार ही नहीं करता कि आज जो बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है, वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेगा या नहीं? यह स्थिति तब है, जब देश के सभी छोटे-बड़े शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है।

एमएसपी से किसानों को भरोसा देने की कोशिश

-अमित बैजनाथ गर्ग

किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन ये सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार तमाम फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है, उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार ये गारंटी देती है, तो फसलों का विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वो धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

हाल ही में केंद्र सरकार ने छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है। यह वृद्धि न्यूनतम 130 रुपए एवं अधिकतम तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं हा के एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि रेपसीड और सरसों के दाम में हुई है। इसमें प्रति क्विंटल तीन सौ रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। असल में एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा! सबसे पहले एमएसपी को समझने की कोशिश करते हैं। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका मकसद किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत साल 1967 में हुई थी। एमएसपी तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सीएसीपी उत्पादन लागत बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसीपी खेती की लागत को तीन हिस्सों में बांटता है। इसमें फसल के भरोसे करने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसलों की एक सूची सरकार को सौंपी थी। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन ये सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार तमाम फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है, उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार ये गारंटी देती है, तो फसलों का विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वो धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी कि जब फसलों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए, तो सरकार इसकी भरपाई करे। वहीं किसानों को धान-गेहूं की फसल की बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती हैं और किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। इससे किसान कर्ज में डूब जाता है और कई मामलों में आत्महत्या कहना है कि एमएसपी व्यवस्था का दबदबा इस सेक्टर में इनोवेशन को हतोत्साहित करेगा। इससे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर रह जाएंगे और जोखिम लेने से डरेंगे, इसलिए किसानों को चावल गेहूं की एमएसपी खरीद के चक्र से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। उनका दावा है कि अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे, तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30 फीसदी बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल की पूरी खरीद की जिम्मेंदारी सरकार को लेनी होगी। किसान जितनी फसल पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी पर पूरी खरीद सरकार और उसकी एजेंसियों को करनी होगी। ऐसा करने से ही किसानों का भला होगा और फसलों का विविधीकरण भी पूरा हो जाएगा। सरकार को अपने फैसले किसानों को ध्यान में रखकर ही लेने होंगे। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता देश के स्थायित्व और सम्मान का विषय है। एमएसपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप तंत्र भी साबित हुआ है। आयात द्वारा खाद्य सुरक्षा कतर, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक आर्थिक आधार वाले देशों के लिए एक व्यवहार्य मॉडल हो सकता है। उनका दावा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दुनिया के बाकी देशों के लिए गेहूं का उत्पादन और निर्यात कर सकते हैं, लेकिन तब कृषि गतिविधियों से जुड़े भारतीयों सहित दुनिया की आधी आबादी बेरोजगार हो जाएगी।

(यह लेखक के स्वय के विचार हैं)

निमोद पैक्स को नेफस्कोब देगा सुभाष यादव पुरस्कार, सहकार नेता ने उपलब्धि पर दी बधाई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । अखिल भारतीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स (नेफस्कोब) की ओर से सुभाष यादव पुरस्कार दिया जाएगा, यह पुरस्कार भारत मंडपम, प्रगति मैदान नई दिल्ली में मंगलवार 26 नवंबर को प्रदान किया जाएगा । इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार नेफस्कोब ने वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की हैं, उल्लेखनीय है कि निमोद समिति का पुरस्कार जीतने का सिलसिला बहुत पुराना है, जिला स्तर पर ऋण वसूली के क्रम में सीसीबी नागौर द्वारा पिछले 35 वर्षों से लगातार 100 प्रतिशत उपलब्धि के लिए प्रतिवर्ष प्रमाणपत्र दिया जा रहा है, वही अपेक्स बैंक द्वारा समिति को कार्य दक्षता का वर्ष 2003-04 एवं 2006-07 में पुरस्कार दिया गया, नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2021 में राजस्थान राज्य स्तरीय प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समिति श्रेणी में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया, इसी प्रकार निमोद समिति को पूर्व में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2011-12 का उत्कृष्टत पुरस्कार तत्कालीन महामहित राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों द्वारा 8 दिसबंर 2012 में प्राप्त हुआ । इसके बाद सुभाष यादव पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए पुन: प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार तथा अखिल भारतीय स्तर पर नेफ्सकोब का वर्ष 2021-22 के लिए तिहरे पुरस्कार दिया गया।

सहकार नेता आमेरा ने दी बधाई

ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एपलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सहकारी साख समितियां एपलाइज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष, ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एपलाइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने निमोद पैक्स के निर्वाचित संचालक मण्डल एवं समस्त कर्मचारियों को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई दी हैं, साथ ही, सहकार नेता ने प्रदेश के सभी पैक्स कर्मियों को सहकार से समृद्धि में पैक्स एज एमएससी में अपनी-अपनी पैक्स को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए आह्वान किया हैं, उन्होने कहा कि निमोद पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियाँ, कारोबार, कार्य संस्कृति, अनुशासन एवं उपलब्धियों से राज्य की सभी सहकारी बैंकों एवं संस्थाओं के प्रबंधन व कार्मिको को प्रेरणा लेकर, अनुसरण कर अपनी संस्थाओं में सहकार से समृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए । वही निमोद पैक्स के अध्यक्ष खेमाराम बुगालिया और संचालक मंडल एवं समिति के मुय शिल्पी सुभाषचंद्र आर्य तथा कार्मिकां को लगातार अनेक स्थानों से सराहना एवं प्रशंसा के समाचार प्राप्त हो रहें है।

खेती का बदला चलन | **बांसवाड़ा के लोगों को गेहूं खिलाने में सक्षम हो रहे किसान**

अब मक्का का गढ़ नहीं रहा बांसवाड़ा, रबी में 75 फिसदी उत्पादन गेहूं का

आठ से 10 किस्में बोते हैं किसान, बीते 10 वर्ष तेजी से बढ़ा रकबा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बांसवाड़ा, कभी मक्का उत्पादन का गढ़ रहा बांसवाड़ा अब भरपूर गेहूं उपजा रहा है। रबी सीजन में मक्का की फसल अब सिमट गई है। इस वर्ष विभाग ने फसलों के प्रस्तावित लक्ष्य 1 लाख 53 हजार 91 हेक्टेयर में से अकेले गेहूं का प्रस्तावित लक्ष्य 115000 हेक्टेयर रखा है, जो कुल फसलों के उत्पादन का 75.11 फीसदी है। बदलाव की इस बयार में किसान गेहूं की कई किस्म चुन रहे हैं। पहले किसान सिर्फ टुकड़ी गेहूं (3077) की बुवाई कर लेते थे, अब खेतों में 10-12 किस्म का

गेहूं बोया जा रहा है। इनमें भी 7 किस्में अधिक प्रचलन में हैं। गेहूं उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने से अब स्थानीय स्तर पर गेहूं की डिमांड पूरी हो रही है। हालांकि गेहूं उत्पादन बढ़ने का विपरीत असर अरहर और चना उत्पादन पर है। दोनों ही फसलों का रकबा बीते वर्षों की तुलना में कम हुआ है।

नॉन कमांड में इजाफा ज्यादा, बांसवाड़ा में नॉन कमांड क्षेत्र में किसानों ने गेहूं को ज्यादा पसंद किया है। इस कारण नॉन कमांड क्षेत्र में पूर्व की तुलना में रकबा बढ़ा है। बीते वर्षों में बनाए गए खुले कुओं से किसानों के लिए सिचाई के लिए पानी की उपल धता बढ़ी। जो गेहूं का रकबा बढ़ने का अहम कारण है।

बांसवाड़ा के किसान चुनते हैं ये किस्में
पहले जहां केवल टुकड़ी गेहूं उगाई जाती थी, अब जिले में कई किस्मों की बुवाई हो रही है। किसान राज 4220, राज 3765, राज 4037, राज 3777, एचआई 1544, डीबीड ल्यू 222, राज 4238, राज 4079 व लोकवन जैसी किस्में अपना रहे हैं।

तापमान माकूल नहीं, लेकिन उत्पादन अच्छा, कृषि विशेषज्ञों की मानें तो बांसवाड़ा का तापमान गेहूं के लिए थोड़ा सत है। बुवाई के समय की पहचान जरूरी है। आदर्श तापमान 10-25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अत्यधिक तापमान (30 डिग्री से अधिक) और कम तापमान (0 डिग्री से कम) गेहूं की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं।

गेहूं के लिए यह तापमान मुफीद

बुवाई के समय :	
20-25 डिग्री से.	
फुटान के समय :	
15-20 डिग्री से.	
दाना भरते समय समय :	
20-25 डिग्री से.	
पकते समय : 25-30 डिग्री से.	

बांसवाड़ा का सामान्य तापमान

माह - अधिकतम तापमान - न्यूनतम तापमान
अक्टूबर - 32.8 - 21.7
नवंबर - 29.4 - 18.5
दिसंबर - 26.2 - 14.5
जनवरी - 5.5 - 13.4
फरवरी - 28.3 - 15.6
मार्च - 33.5 - 20.2
अप्रैल - 38.4 - 24.5

तापमान डिग्री सेल्सियस में, बदलाव संभव

जिले में ये रहा गेहूं का रकबा

वर्ष : रकबा हेक्टेयर
2017-18 : 84265
2018-19 : 87641
2019-20 : 85873
2020-21 : 94516
2021 -22 : 98268
2022-23 : 126465
2023-24 : 108692
2024-25 : 115000

(प्राप्त जानकारी के आधार)

बुवाई के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा परफेक्ट

किसान नवंबर के पहले पखवाड़े यानि 15 तारीख के पहले बुवाई कर दें, ताकि फरवरी तक दान पक जाए। चूंकि बांसवाड़ा में फरवरी में तापमान बढ़ने लगता है, ऐसे में गेहूं का दाना पक नहीं पाता और छोटा रह जाता है।

डॉ. हरगिलास मीणा, जोनल डायरेक्टर, कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट, बांसवाड़ा

सिंचाई व्यवस्था से किसानों को मिला संबल

बीते वर्षों में सिंचाई व्यवस्था बढ़ी है। नॉन कमांड क्षेत्र में किसानों को काफी संबल मिला। ओवरऑल गेहूं का रकबा बढ़ा है। फसल का समय 110 से 120 दिन होता है।

डॉ .दलीप सिंह यादव, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), बांसवाड़ा

बढ़ गईं कई प्रजातियां

पूरे जिले में गेहूं की उपज का अंदाजा लगाना सहज नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में किस्में काफी बढ़ गई हैं। पहले टुकड़ी गेहूं आता था, लेकिन अब स्थानीय किसान कई वैरायटी के गेहूं उत्पादित करने लगे हैं। व्यापारी भी काफी बढ़ गए है, जो इंगित करता है कि जिले में गेहूं की उपज बढ़ी है।

सोनू दोसी, गेहूं व्यापारी

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम......
ग्राम...... पोस्ट......
तहसील...... जिला......
फोन...... पिन कोड......
राशि (रुपए) ...... बैंक का नाम......

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134

Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

सिरोही सीसीबी में आठ वर्षो से लंबित डीपीसी करने की सहकार नेता आमेरा ने उठाई मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रान्तीय महासचिव सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने सहकारिता विभाग पंजीयक को ज्ञापन देकर सिरोही सीसीबी में पिछले आठ वर्षो से लंबित डीपीसी बैठक कर पात्र कर्मियों को पदोन्नत किए जाने की मांग उठाई हैं । सहकार नेता ने ज्ञापन के जरिए बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने 4 मार्च 2024 को आदेश जारी कर वर्ष 2023-24 तक की सभी लंबित डीपीसी 31 मार्च तक सुनिश्चित करने के निर्देश के बावजूद सिरोही सीसीबी प्रबंधन द्वारा पिछले आठ वर्षो से डीपीसी नहीं की जा रही हैं, जो राज्य सरकार के आदेशों की सरासर अवहेलना हैं । वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा कार्मिको की वर्ष में दो बार डीपीसी किए जाने के निर्णय व घोषणा की भी सिरोही सीसीबी प्रबंधन द्वारा मनमानीपूर्ण अवहेलना के चलते सहकार नेता आमेरा ने सहकारिता विभाग पंजीयक से सिरोही सीसीबी प्रबंधन को अविलंब डीपीसी बैठक बुलाने के संबंध में आदेश जारी करने की मांग उठाई है। गौरतलब हैं किहाल ही में सहकार नेता आमेरा एआईबीओए की बैठक में शिरकत करने आबूरोड़ पहुंचे थे, इस दौरान सिरोही सीसीबी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मुलाकात कर महासचिव को लंबित डीपीसी व अन्य मांगो से अवगत करवाया था ।

नियमित ऑफ़िसिएटिंग अलाउंस का नहीं किया जा रहा भुगतान

सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने बताया कि बैंक में गत डीपीसी 21 जून 2016 को वर्ष 2015-16 तक के लिए की गई थी, उसके उपरांत आज दिन तक कोई डीपीसी की बैठक आहुत नहीं हुई हैं, जिससे कर्मचारियों व अधिकारियों को पिछले आठ वर्षो से उनके पदोन्नति के वाजिब हक़ से वंचित कर उन्हें आर्थिक नुकसान दिया जा रहा हैं, इतना ही नहीं बैंक में रिक्त पदों के चलते बैंकिंग सहायक से ही शाखा प्रबंधक के पदों पर काम लेकर उन्हें नियमित ऑफ़िसिएटिंग अलाउंस का भी भुगतान नहीं करके उनके हितों के साथ दोहरा कुठाराघात किया जा रहा है । उन्होने कहा कि सिरोही सीसीबी में कुल स्वीकृत 96 पदों के विरुद्ध मात्र 32 कार्मिक कार्य कर रहे है, जिससे 64 पद रिक्त हैं, वही इनमें से अधिकारी केटीगिरी के अधिकांश पद पदोन्नति से ही भरे जाने है ।

जिला कलक्टर ने चूरू सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों, कार्मिकों के साथ बैठक कर समुचित दिशा-निर्देश दिए

सहकारी बैंक के अधिकारी टाइमलाइन निर्धारित कर लक्ष्य प्राप्त करें : सुराणा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

चूरू, । जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने डीओआईटी वीसी सभागार में दी चूरू सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय एवं सभी शाखा कार्यालय के अधिकारियों, कार्मिकों के साथ बैठक कर समुचित दिशा-निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि बैंक के अधिकारी अपने लक्ष्य को टाइमलाइन निर्धारित कर पूरा करें तथा बैंक के वसूली कार्य को गति दें। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाओं के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंकिंग एक व्यवसायिक गतिविधि है, इसमें ऋण दिए जाने के साथ-साथ वसूली भी उतनी ही आवश्यक है। बैंक की समृद्धि के लिए जरूरी है कि निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध एवं समुचित पूर्ति हो तथा किसानों व आमजन को बैंक सेवाओं का समुचित लाभ मिलता रहे। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बैंक अधिकारी फील्ड में जाएं तथा किसानों को मोटिवेट करते हुए निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। जिला कलक्टर सुराणा ने बैठक के दौरान अमानतों की लक्ष्य पूर्ति, अल्पकालीन फसली ऋण की मांग वसूली, अकृषि निवेश ऋणों की वसूली, कृषि निवेश ऋणों की वसूली, गैर फसली ऋण वितरण, एनपीए वसूली, एक मुश्त समाधान योजना 2023, ग्रामीण आजीविका योजना में वसूली, केवाईसी, रिस्क कैटिगराइजेशन, पेंडिंग एएमएल अलर्ट, सीआईसी रिपोर्ट रिजेक्शंस, एनपीसीएल से आधार मैपिंग, चेक बुक आवेदनों एवं जारी करने सहित बिंदुओं पर चर्चा कर विस्तृत दिशा- निर्देश दिए। चीफ मैनेजर सर्वेश वर्मा ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान एमडी मदनलाल, एपीआरओ मनीष कुमार, ईओ अमीलाल सहारण,वरिष्ठ प्रबंधक हजारी राम, वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन सुरेन्द्र सिंह भाटी, राजपाल सिंह, संगीता राठौड़, निष्ठा माथुर, विपिन मुंजाल, संजय पूनिया, विरेन्द्र सिंह, अभिषेक भारद्वाज, सहित समस्त बैंक शाखों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

ऋण खातों में वसूली के लिए किए जाएं अधिकतम प्रयास

जिला कलक्टर सुराणा ने कहा कि बैंक कर्मचारी होने के नाते हमारे नैतिक दायित्व भी बनते हैं। बैंक की मजबूत साख एवं अच्छी आय के लिए हम अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करें तथा अपेक्षित प्रगति लाएं। इस वर्ष अंचल में फसलों की अच्छी पैदावार हुई है। इसलिए ऋण वाले खातों में वसूली के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएं। बैंक के जिन ऋण खाते में वापस वसूली नहीं हो रही है, उनमें कार्मिकों की जिमेदारी तय करें।

नाराजगी जताते हुए लगाई फटकार

इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त शाखा कार्यालयों के विभिन्न गतिविधियों में निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य पूर्ति की चर्चा की। सालासर एवं सुजानगढ़ शाखा में लक्ष्य पूर्ति में कमी रहने पर जिला कलक्टर ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। इसी के साथ चूरू को-ऑपरेटिव के प्रधान कार्यालय के प्रबंधक कुलदीप परिहार के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि कार्मिकों की जिमेदारी तय हो। अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वालों व लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही करें।

सभी शाखों की नियमित रूप से करें मॉनीटरिंग

जिला कलेक्टर ने बैंक एमडी मदनलाल से कहा कि सभी शाखों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करें। सुबह-शाम बैंक अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति ग्रुप पर लें और परफॉर्मेंस के लिए किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट भिजवाएं। इसी के साथ सभी बैंक अधिकारी नियमित डायरी मेंटेन करें एवं रिपोर्टिंग फॉर्मेट डेवलप करें। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी रिजल्ट के लिए एफर्ट करें। कार्मिक बैंकर्स की तरह काम करें। फील्ड में रहें और किसानों को मोटिवेट करें। बैंक अधिकारी किसानों व कृषि के अपने मूल काम पर फोकस करें तथा सहगामी गतिविधियों पर भी कार्य करें।

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

ग्राम पंचायत खेजड़याली
पंचायत समिति चितलवाना, जिला-सांचौर

विनम्र अपील

ग्राम को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य बनावावे। वृक्ष लगाए, खुशहाली लाएं। पानी बचाए, जीवन बचाए। सरकार की गोचर, ओरण, नाड़ी, बिलानाम व खालसा भूमि पर अतिक्रमण नही करे। केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेवें।

नेनुदेवी कोली
सरपंच

रमाकांत
ग्राम विकास अधिकारी

निमोद सहकारी समिति व्यवस्थापक ने राजीविका के आरोप को बताया बेबुनियाद

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नागौर । जिले की निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से राजीविका समूह के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप कर समिति के गठित समूह तोड़ने के प्रयास के संबंध में जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन को एक पत्र लिखा गया हैं, जिसके मुताबिक ग्रामीण आजीविका विकास परिषद मौलासर द्वारा समिति पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, राजीविका समूह मौलासर द्वारा सहकारी समिति के गठित समूह को तोड़ने के सबंध में 23 अगस्त 2024 को समिति अध्यक्ष खेमाराम बुगालिया ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर को एक पत्र लिखा गया था, उसके पश्चात राजीविका मौलासर ने 27 अगस्त को एक पत्र लिखकर समिति पर राजीविका समूह से महिलाओं को हटाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया हैं । समिति अध्यक्ष की ओर से सहकारिता विभाग पंजीयक को भेजे गए पत्र के अनुसार निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति में वर्ष 2009-10 से स्वयं सहायता समूह के लिंकेज से करीब 3000 महिलाएं वित्त पोषण कर रही हैं । समिति ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि स्थानीय राजीविका कार्यकर्ता अलग से मेहनत नहीं करके हमारी समिति के पूर्व गठित समूह में ही हस्तक्षेप कर सदस्यों को राजीविका समूह से जोड़ते रहते हैं । जिससे दोहरी सदस्यता के चलते समूहों में शुद्धता नहीं बनी रहती हैं और समूह के सभी सदस्यों का वित्तपोषण रुक जाता हैं ।

10 करोड़ की सी.सी लिमिट

निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष खेमाराम बुगालिया की ओर से सहकारिता विभाग पंजीयक को भेजे गए पत्र के अनुसार समिति में करीब 183 स्वयं सहायता समूह लिंक हैं, जिनमें 3000 महिला सदस्य हैं, इन समूहों की बचत राशि करीब 1 करोड़ 25 लाख हैं और सी.सी.लिमिट 10 करोड़ रुपए हैं । उल्लेखनीय हैं कि निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति वरन जिले में ही नहीं बल्कि देश-प्रदेश में पैक्स की दृष्टि से अग्रणी पंक्ति में शामिल हैं, निमोद सहकारी समिति को सीसीबी नागौर द्वारा पिछले 35 वर्षो से ऋण वसूली के लिए उपलब्धि प्रमाणपत्र तो अपेक्स बैंक द्वारा 2003-04 एवं 2006-07 में कार्य दक्षता पुरस्कार दिया गया, इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2011-12 का उत्कृष्टत पुरस्कार तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों में 8 दिसबंर 2012 में निमोद सहकारी समिति को प्राप्त हुआ था। वही आने वाले 26 नवंबर को एक बार फिर नेफस्कोब की ओर से निमोद सहकारी समिति को सुभाष यादव अवार्ड देकर पुरस्कृत किया जाएगा ।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की केंद्रीय समिति बैठक आबूरोड में सपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । देश के कॉमर्शियल, निजी, ग्रामीण एवं सहकारी बैकों में कार्यरत अधिकारियों के संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की दो दिवसीय राष्ट्रीय केन्द्रीय समिति की बैठक 9-10 नवंबर को आबू रोड में चेयरमैन वी अनिल कुमार (हैदराबाद) अश्विनी प्रधान (जम्मू कश्मीर) की संयुक्त अध्यक्षता में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मानसरोवर आवासीय परिसर में संपन्न हुई । इस दौरान एआईबीओए महासचिव एस नागराजन ने बैठक में महासचिव रिपोर्ट के साथ एजेंडा पेश किया, जिस पर विभिन्न राज्यों से तीस प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया ।

वही सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने बैठक को संबोधित करते हुए एजेंडे पर विचार रखें, आमेरा ने बताया कि एआईबीओए की दो दिवसीय बैठक में बैंकिंग उद्योग की दिशा व दशा, सरकार व प्रबन्धन की रीति नीति के साथ मुख्य माँगे बैंकों में वर्क लाइफ बैलेंस के लिए पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह, रेग्युलेटेड वर्किंग ऑवर लागू करने, दो लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने, ओपीएस पेंशन लागू करने, गैर बैंकिंग उत्पाद बिकी पर रोक लगाने, सहकारी बैंकिंग ढाँचे में टू टियर व्यवस्था लागू कर अपैक्स बैंक में सीसीबी मर्जर कर ग्रामीण बैंक की तरह एक राज्य में एक सहकारी बैंक बनाने की भारत सरकार से मांग की गई ।

बैठक में सभी माँगो पर प्रस्ताव पारित कर देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया । सहकार नेता आमेरा ने बताया कि बैठक के साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा बैंक अधिकारियों के वर्क लाइफ बैलेंस व स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दो दिन मैडिटेशन वर्क शॉप भी आयोजित कर अभ्यास शेषन करवाए गए । संस्थान द्वारा सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद कर प्रतीक चिन्ह भेट किए गए। इस दौरान बैठक में काश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यो से कॉमर्शियल, निजी, ग्रामीण एवं सहकारी बैकों से अधिकारी नेताओं ने भाग लिया । एआईबीओए राजस्थान से महासचिव नरेश शर्मा, उप महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा,

सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में हस्तगत किया 10 लाख का चेक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा भूमि धारक किसानों को सीजनली अल्पकालीन फसली ऋण मुहैया कराया जा रहा हैं, इस योजना के साथ ही किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना एवं सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत अनिवार्य रुप से बीमा किया जा रहा हैं, इसी क्रम में जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक की रानीवाड़ा शाखा कार्यक्षेत्र की जैतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसान कपूराराम पुरोहित का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया गया था । उनकी सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के पश्चात सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में क्लेम राशि 10 लाख रुपए स्वीकृत होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक रानीवाड़ा शाखा प्रबंधक जितेन्द्रसिंह शेखावत एवं कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक गणपतसिंह बालोत ने मृतक किसान की धर्मपत्नी पंखू देवी को 10 लाख रुपए की राशि का चेक हस्तगत किया गया है। इस दौरान बैकिंग सहायक मनीष फुलवानी, जैतपुरा समिति व्यवस्थापक दिनेश कुमार चौधरी, मेड़ा सहकारी समिति से व्यवस्थापक जब्बरगिरी आदि उपस्थित रहे।

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

ग्राम पंचायत सुराचंद
पंचायत समिति चितलवाना, जिला-सांचौर

विनम्र अपील

ग्राम को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य बनावावे। वृक्ष लगाए, खुशहाली लाएं। पानी बचाए, जीवन बचाए। सरकार की गोचर, ओरण, नाड़ी, बिलानाम व खालसा भूमि पर अतिक्रमण नही करे। केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेवें।

कंचन कंवर
सरपंच

रमाकांत
ग्राम विकास अधिकारी

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

ग्राम पंचायत सुथड़ी
पंचायत समिति चितलवाना, जिला-सांचौर

विनम्र अपील

ग्राम को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य बनावावे। वृक्ष लगाए, खुशहाली लाएं। पानी बचाए, जीवन बचाए। सरकार की गोचर, ओरण, नाड़ी, बिलानाम व खालसा भूमि पर अतिक्रमण नही करे। केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेवें।

मरियत
सरपंच

मेहराराम
ग्राम विकास अधिकारी

खरीफ में 1647 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की संभावना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, । कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों केवल खरीफ के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। ये अनुमान मुख्यतः राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किये गये हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यों से प्राप्त फसलों के क्षेत्रफल को रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ सत्यापित किया गया है। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उद्योग और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ वर्तमान खरीफ मौसम के लिए उनकी राय और विचार प्राप्त करने हेतु हितधारक परामर्श करने की पहल की है। अनुमानों को अंतिम रूप देते समय इन पर भी विचार किया गया है। पहली बार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से किए जा रहे डिजिटल क्राप सर्वे डीसीएस के आंकड़ों का उपयोग क्षेत्रफल के अनुमानों को तैयार करने के लिए किया गया है। यह सर्वे, जो मैनुअल गिरदावरी प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए परिकल्पित किया गया है, मजबूत फसल क्षेत्रफल अनुमान प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा राज्यों जिसमें खरीफ 2024 में शत प्रतिशत जिलों को डीसीएस के अंतर्गत कवर किया गया है। परिणामस्वरूप विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चावल के अंतर्गत क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 124.59 लाख टन अधिक है। चावल, ज्वार और मक्का के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। वर्ष 2024-25 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन 1199.34 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 66.75 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ चावल उत्पादन से 114.83 लाख टन अधिक है। खरीफ मक्का का उत्पादन 245.41 लाख टन एवं खरीफ पोषक यानी मोटे अनाजों का उत्पादन 378.18 लाख टन अनुमानित है। इसके अलावा 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनों का उत्पादन 69.54 लाख टन अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 257.45 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के खरीफ तिलहन उत्पादन की तुलना में 15.83 लाख टन अधिक है। वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ मूंगफली का उत्पादन 103.60 लाख टन एवं सोयाबीन का उत्पादन 133.60 लाख टन अनुमानित है। इस दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 4399.30 लाख टन अनुमानित है। कपास का उत्पादन 299.26 लाख गांठें प्रति गांठ 170 किग्रा. अनुमानित है। पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 84.56 लाख गांठें प्रति गांठ 180 किग्रा अनुमानित है। फसलों की उपज के अनुमान मुख्य रूप से पिछली प्रवृत्तियों तथा सामान्य उपज, अन्य जमीनी स्तर के इनपुट और अपेक्षाओं पर आधारित हैं। यह उपज फसल कटाई समय के दौरान फसल कटाई प्रयोगों के जरिए प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर संशोधित की जाएगी, जो अंततः उत्पादन अनुमानों में परिलक्षित होगी।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, शुक्रवार, 15 नवंबर 2024
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पदों पर नियुक्तियों से लेकर चार्ज को लेकर खेला जा रहा खेल, अस्थाई के व्यवस्थापक कर रहें करोड़ों का करोबार

नियमों की पालना के बजाए उपकृत करने की चल रही परपंरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सहकारी भर्ती बोर्ड गठन को लेकर सहकारिता विभाग वर्ष 2017 से निरतंर आदेश एवं निर्देश जारी कर रहा हैं, लेकिन जोधपुर मुख्यालय में खंडीय अधिकारी का कार्यालय होने के बावजुद सीसीबी और उप रजिस्ट्रार के कानों में इसकी भनकार तक नहीं पहुंच रही हैं, ऐसा इसलिए कह रहें हैं क्योकि वर्ष 2017 में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन के साथ ही सहकारी समितियों में कर्मियों की प्रस्ताव प्रणाली नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक होने के बावजुद जोधपुर सीसीबी कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2017 के पश्चात नई नियुक्तियां हो गई और इसका चलन नियमों को धात बताकर बैकडेट प्रस्ताव के जरिए चला हैं। इस नियम विरुद्ध प्रक्रिया पर कार्यवाही करने के बजाए खंडीय अधिकारी, सीसीबी के अधिकारी और उप रजिस्ट्रार कार्यालय इसे संरक्षण देने में लगे हुए हैं, वही अवैध नियुक्तियां पाकर अपात्र व्यक्ति स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित तक हो गए हैं इन अपात्रों को उपकृत करने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के स्टे को भी दरकिनार कर कागजी कार्यवाही में अक्टूबर 2023 को ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण होने का आदेश जारी कर दिया, जिससे कई अपात्र भी बहती गंगा में हाथ धोकर ''मैनेजर साहेब'' बनकर बैठ गए है। गौरतलब हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ ने स्क्रीनिंग चयन प्रक्रिया पर 30 सितंबर 2022 को स्थगन आदेश दिया था, जिसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर ने समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार को पत्र भी लिखा था

2018 में विभाग ने दिया जवाब

राज्य में भजनलाल सरकार के संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने 14वीं विधानसभा में लूणी पंचायत समिति अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों की जानकारी के संबंध में 24 जनवरी 2018 को एक अतांराकित प्रश्न किया था, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने 39 सहकारी समितियों के कार्मिकों की जानकारी दी, जिसमें ऐसे कई कार्मिकों का नाम नहीं हैं, जो आज वर्तमान समय में सहकारी समितियों में व्यवस्थापक बनकर बैठे हैं ।

नाम का उल्लेख नहीं और व्यवस्थापक पद पर आसीन

जिले में उदाहरण के तौर पर डोली एवं पाल ग्राम सेवा सहकारी समिति को समझा जा सकता हैं, जहां, विधानसभा में वर्ष 2018 में विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में डोली सहकारी समिति में अनंत कुमार को व्यवस्थापक एवं गगन विसन को सहायक व्यवस्थापक वही पाल में प्रतापसिंह को व्यवस्थापक बताया गया हैं, जबकि वर्तमान में डोली सहकारी समिति में भंवरलाल पटेल और पाल सहकारी समिति में दीपक व्यास को मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक बनाया हुआ हैं, वही घेवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद का चार्ज गोरधनराम (गगाड़ी) को दिया हुआ हैं, जबकि गगाड़ी समिति में फसली ऋण पोर्टल की आई.डी धर्माराम के नाम से बनाकर समिति का कार्य संपन्न करवाया जा रहा हैं, ऐसी स्थिती जोधपुर जिले की दर्जनभर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद को लेकर बनी हुई हैं।

रिकॉर्ड में अस्थाई और पांच समितियां का चार्ज

रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर में अतिरिक रजिस्ट्रार बैकिंग तत्कालीन भोमाराम द्वारा व्यवस्थापक चार्ज को लेकर वर्ष 2020 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें एक मूल समिति और एक अन्य समिति का चार्ज देने के निर्देश जारी किए गए थे, जबकि जोधपुर जिले की बेरु, दईकड़ा, लोडी दयाजागरा, इन्द्रोका, नारवा सहकारी समिति का चार्ज अस्थाई व्यवस्थापक ओमप्रकाश के पास हैं, इसी प्रकार, सुनिल नाम के अस्थाई व्यवस्थापक के पास मौखेरी, चैनपुरा, गांधीसागर एवं प्रेमचंद के पास सुरपुरा, बालरवा, जाजीवाल खिवांन व हजारी राम के पास बड़लया, नारनाड़ी, रियान समिति का चार्ज दिया हुआ हैं, जिससे प्रतित हो रहा हैं कि जोधपुर सीसीबी में केवल-और-केवल अपने ही नियम कायदे एवं कानून चल रहें हैं ।

रिकॉर्ड में पद रिक्त और समितियां में मुख्य कार्यकारी का पदभार

सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले की आगोलाई, ढाढणियां, गिलाकौर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 1984 से व्यवस्थापक का पद रिक्त हैं, इसी प्रकार शेरगढ़, सुवालिया में 2008 से तो वही 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1984 से लेकर 2017 तक व्यवस्थापकों के पद खाली पड़े हैं और वित्त दाता बैंक द्वारा सहकारी भर्ती बोर्ड को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की अभ्यर्थना भेजने के बजाए अयोग्ताधारी लोगो को समितियों में मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक का चार्ज थमाया हुआ हैं, इतना ही नहीं जिले की 50 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकीय सेवानियम 2008 में निहित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किए बिना ही व्यवस्थापकों की समिति स्तर से नियुक्ति करने के पश्चात पूर्व समय में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से इनका नियमितिकरण भी कर दिया गया हैं ।

नहरी क्षेत्र के किसान खाद के लिए हो रहे परेशान, खाली पड़े सहकारी समितियों के गोदाम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सांचौर । नर्मदा नहरी क्षेत्र के किसानों को डीएपी-खाद के लिए बुवाई के दौर में परेशान होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अधिकांश सहकारी समितियों में ही डीएपी नहीं है वहीं दुकानों के गोदाम भी खाद से रीते पड़े हुए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी की फसलों में किसानों को डीएपी खाद की सख्त जरूरत है। किसानों को कहीं भी जरूरत के अनुसार डीएपी नहीं मिल रहा। किसान डीएपी के लिए भटकने को मजबूर हैं। सहकारी समितियों के साथ ही दुकानों के गोदाम भी खाद की कमी से रीते पड़े है। मांग अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से डीएपी की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा रखी हैं। मुंह मांगा दाम देकर भी किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मिल रहा। रोजाना किसान सहकारी समितियों व दुकानों पर भटक रहे हैं, लेकिन सब जगह डीएपी नहीं होने का जवाब मिल रहा है। डीएपी के अभाव में कई किसान बुवाई से भी पीछे हट रहे हैं। जिससे बुवाई भी पिछड़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि खेतों में अधिकांश किसानों ने सरसों, जीरा, इस्बगोल जैसी फसलों की बुवाई कर दी। किसान अंकुरित फसलों में सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के दौरान ही किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ रही है। वहीं तापमान अनुकूल होने से गेहूं की बुवाई भी शुरू होने लगी है। गेहूं की बुवाई में भी किसानों को डीएपी की जरूरत है। लेकिन डीएपी कहीं नहीं मिल रहा। डीएपी की किल्लत का आलम यह है कि किसान सब काम छोड़कर डीएपी के बंदोबस्त के लिए दुकानों व सहकारी समितियों में चक्कर काटने को मजबूर हैं। गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है, ऐसे में मांग बढ़ने के बावजूद आपूर्ति कम हो रही है।

भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं शर्मा बीज भण्डार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने भीलवाड़ा में क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल द्वारा भीलवाड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा ली गई तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। शासन सचिव द्वारा जिले के अधिकारियों द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर डीबीटी योजनाओं की प्रगति, एसएनए स्पर्श एवं गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति की चर्चा की गई। शासन सचिव द्वारा कार्यालय में ई-फाइलिंग, उर्वरक नमूना प्रक्रिया, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, बुवाई सूचना संकलन की प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली एवं विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि विभाग की योजनाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करें तथा कृषि पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचा कर उन्हें लाभान्वित करें।शासन सचिव ने कृषि भवन निरीक्षण के उपरान्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा एवं शर्मा बीज भण्डार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इसके उपरान्त कृषि विज्ञान केन्द्र भीलवाड़ा पर उन्नत कृषि प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक कृषि श्री रामावतार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) गोपाल लाल कुमावत, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) गोपाल लाल कुमावत, संयुक्त निदेशक उद्यान श्री महेश चेजारा एवं परियोजना निदेशक आत्मा श्री शंकर सिंह राठौड़ एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

183.22 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से किया भुगतान

जयपुर,। राज्यभर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर दीपावली से ठीक पहले दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इससे राज्यभर में 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, फैडरेशन से सम्बद्ध अलग-अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों को दीपावली से पूर्व 20 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश अलग से वितरित किया गया है। यह जानकारी देते हुए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर आरसीडीएफ द्वारा डीबीटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत अनुदान और लाभांश वितरण से खुशी की लहर है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन में लगातार हो रही बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा योगदान है।

कॉनफैड के ग्रीन इनीशियेटिव में कृभको ने मिलाया हाथ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। कॉनफैड द्वारा अपने ग्रीन इनीशियेटिव प्रोजेक्ट के तहत सहकार भवन स्थित उपहार स्टोर पर मीठे पानी की सब्जियां और ताजे फल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस कड़ी में आज कृभको ने कॉनफैड के साथ ''नो प्लास्टिक यूज'' कैंपेन को बढ़ावा देने के लिये सब्जी और फल की खरीददारी करने वालों को कपड़े के मजबूत बैग उपलब्ध कराये। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कॉनफैड द्वारा अपने स्टोर्स पर ''नो प्लास्टिक यूज'' कैंपेन को सपोर्ट करने के लिये पहले से ही कपड़े के कैरी बैग उपलब्ध करा रहा है। आज इस मुहीम में कृभको ने बार-बार प्रयोग में लाने योग्य कपड़े के बैग उपलब्ध कराये हैं ताकि प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि आजकल दैनिक आवश्यकता में प्लास्टिक का

उपयोग एक चरम सीमा को पार कर चुका है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। यह अंततः आमजन के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। शासन सचिव ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिमेदारी है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिये साफ और सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के प्रयोग को कम करके हम ''स्वच्छ जयपुर'' अभियान में भी योगदान दे सकते हैं। इसलिये हमें बाजार से सामान खरीदते समये अपना कैरी बैग अवश्य ले जाना चाहिये।

जिला कलक्टर ने सायला पंचायत समिति में जनसुनवाई कर समस्याओं का किया निस्तारण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी एवं संवेदनशील सुशासन के लिए आमजन की परिवेदनाओं व समस्याओं के त्वरित गति से समाधान के लिए जिले में ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें आमजन की परिवेदनाएँ प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने सायला पंचायत समिति सभागार में आयोजित उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के साथ ही जनता की समस्याओं पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए परिवादों के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए।

जम्भेश्वर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बासड़ाधनजी

किसानों से अपील
एकमुश्त समाधान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की अरणाय शाखा में सपर्क करें।

श्रीमती धीरेन्द्रकंवर
अध्यक्ष
श्री पीराराम गर्ग
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
शिवनाथसिंह राजपुरोहित
उपाध्यक्ष

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष लेखा परीक्षा के उपरांत लेखा परीक्षा रोटेशन विभागीय ऑडिटर द्वारा संपन्न करने के निर्देश

30 सितबंर तक सहकारी सोसायटियों का ऑडिट कार्य संपन्न नहीं होने पर लेखा परीक्षकों की होगी पुनर्नियुक्ति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की सहकारी सोसायटियों की ऑडिट को लेकर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की ओर से गत दिनों एक परिपत्र जारी किया गया हैं, यह परिपत्र निर्धारित तिथि 30 सितबंर से पूर्व सहकारी सोसायटियों का वार्षिक वैधानिक लेखा विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण जारी हुए हैं, इनमें अब सीए फर्म के लिए संस्थाओं की सेंया के साथ सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य की अधिकत्तम अवधि भी निर्धारित की गई है। जिसमें सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षक के रुप में फर्म को अधिकत्तम 30 सहकारी संस्थाओं की सेंया तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक के लिए अधिकत्तम 15 सहकारी संस्थाओं की सेंया निर्धारित की गई हैं । साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, अरबन कॉपरेटिव बैंकों के अतिरिक्त अन्य सहकारी सोसायटियों की सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष लेखा परीक्षा के उपरांत लेखा परीक्षा रोटेशन विभागीय ऑडिटर द्वारा संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं, गौरतलब हैं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 (2) के अनुसार विहित पैनल में से लेखा परीक्षक की नियुक्ति 31 मई तक आवश्यक रूप करने और धारा 54 (3) के तहत वित्तीय वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा उस वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर करवाए जानेका दायित्व सबन्धित सहकारी सोसायटी का हैं वही परिपत्र के मुताबिक निर्धारित प्रावधानानुसार यदि सहकारी समिति द्वारा विभागीय ऑडिटर से लेखा परीक्षा करवाए जाने का निर्णय लिया जाएगा, तो उस प्रस्ताव को निर्धारित समय यानि 31 मई से पूर्व राज सहकार पोर्टल पर अपलोड करना होगा । इतना ही नहीं अगर 31 मई तक सहकारी संस्था द्वारा लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं होती हैं, तो संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय को 15 जून से पूर्व लेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी होगी ।

अधिकत्तम कार्य दिवस निर्धारित

सहकारिता विभाग पंजीयक की ओर से जारी परिपत्र में वार्षिक वैधानिक लेखा परीक्षा का कार्य निर्धारित समयावधि में संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शीर्ष बैंक का अधिकत्तम 2 माह की अवधि में तथा केंद्रीय सहकारी संस्थाओं, पीएलडीबी, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, अरबन कॉपरेटिव बैंक के लिए भी 2 माह की अवधि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार केवीएसएस, सहकारी संघ, होलसेल भण्डार के लिए 20 दिवस एवं सहकारी समितियों के लिए 5 दिवस तथा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के लिए 3 दिवस निर्धारित की गई हैं, वही अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए अधिकत्तम 3 दिवस की अवधि निर्धारित की गई है।

हानि वाली समितियों में ऑडिटर की नियुक्ति अनिवार्य

परिपत्र के अनुसार संबंधित विभागीय कार्यालय द्वारा वित्तीय असन्तुलन एवं निरतंर हानि वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में विभागीय ऑडिटर की नियुक्ति करना अब अनिवार्य है। साथ ही संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा मासिक अपेक्षित लक्ष्य निर्धारण कर निरंतर मोनेटरिंग करते हुए सहकारी संस्थाओं का वार्षिक वैधानिक लेखा 30 सितबंर से पूर्व पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए है। वही अगर सहकारी सोसायटियों द्वारा 30 सितबंर तक लेखा परीक्षा पूर्ण नहीं करवाया जाता हैं, तो संबंधित रजिस्ट्रार तत्काल लेखा परीक्षक की पुनर्नियुक्ति कर अविलंब लेखा परीक्षा कार्य पूर्ण करवा सकता है।

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर होगी कार्यवाही

ऑडिट को लेकर जारी परिपत्र के मुताबिक अगर किसी सहकारी सोसायटी द्वारा लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करवाने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाता हैं, या ऑडिट नहीं करवाई जाती हैं, तो उस सोसायटी के विरुद्ध परीक्षक द्वारा नोटिस जारी कर अविलंब संबंधित रजिस्ट्रार को लिखित्त में अवगत करवाना होगा । इस स्थिती में संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा अधिनियमानुसार कार्यवाही करने का प्रकरण तैयार कर संबंधित खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप, सहायक रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, जिस पर संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी के विरुद्ध अधिनियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।